

विचार मंथन

जनता के बीच जाइए

विषयक का पास एक हा रास्ता है कि वह राजनीति का तराका बदल। सर्वसत्तावादी सरकारों पर लगाम सिर्फ जनता के बीच रहते हुए और उसे संगठित करते हुए ही लगाई जा सकती है। मगर विषयक इसके लिए तैयार नहीं दिखता। अब यह लगभग दस साल का अनुभव है कि वर्तमान भाजपा सरकार संसदीय जवाबदेही को नहीं मानती। ना ही संसद की प्रक्रियाओं का आदर करती है। जिस थोक भाव में संसदों का निलंबन अब हुआ है, उससे यह बात पृष्ठ हुई है कि गुजराते वक्त के साथ सत्ता पक्ष का यह रुख और कठोर होता जा रहा है। सोमवार तक कुल 92 संसदों को निलंबित किया जा चुका था। राज्यसभा के निलंबित हुए 46 सदस्यों में से 35 को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। बाकी 11 संसदों को उनके व्यवहार पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। उधर लोकसभा में निलंबित 46 संसदों में से तीन संसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। बाकी पूरे सत्र के लिए सम्पेंड किए गए हैं। आखिर इन संसदों का दोष क्या था? वे 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मसले पर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे थे। क्या यह मांग इतनी बड़ी थी, जिसको लोकर इतना बड़ा विवाद खड़ा होता? मगर ऐसा हुआ है, तो उसके निष्कर्ष स्पष्ट हैं। सरकार ने बता दिया है कि वह विषय और विरोध को स्वीकार नहीं करती। तो अब प्रश्न विषय के सामने है कि वह क्या करेगा? लोकतंत्र की हत्या हुई, जैसे जैसे बयान अब कोई प्रभाव पैदा नहीं करते। गौरतलब है कि सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिष्ठा मलिलाकार्जुन खडगे ने कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार ने संसद और लोकतंत्र पर हमला किया है। उन्होंने ये अंदेशा भी जताया कि विषय की गैर-हजिरी में सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिल पास करा लेंगी। ये बात भी बहुत दमदार नहीं है, क्योंकि सरकार विषय की मौजूदगी में भी मनमाफिक ढंग से विधेयक पास कराती रही है। ऐसे में विषय के पास एक ही रास्ता है कि वह राजनीति का तरीका बदले। सर्वसत्तावादी सरकारों पर लगाम सिर्फ जनता के बीच रहते हुए और उसे संगठित करते हुए ही लगाई जा सकती है। मगर विषय इसके लिए तैयार नहीं दिखता। इसलिए वह अपनी जगह छोता चला गया है।

पद्मावतीपाटी का लेक मिमिक्री भी मुद्दा है?

आधी संसद
उत्तरायण

औजार बन गयी है। गरीमत ये है कि विक्ष पवित्रीन आधी सांसद ने इसे अभी भारतीय दंड संहिता के किसी अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से अपराध घोषित नहीं किया है। भारतीय अपराध संहिता के लिए भी मन देखे जा रहे हैं। कौन इटली वाला है और कौन नागपुर वाला?

की सियासत के युग में अब इस आवश्यक विधा पर भी हमला किया जा रहा है, वो भी रो-रोकर, सांसद में खड़े हो-होकर। जबकि इस देश ने संसद में अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गयी हर मिमिक्री को पूरी उदारता से न सिर्फ देखा बल्कि उसका आनंद लिया। उस पर कभी टसुए नहीं बहाये, उसे कभी जातीय या पेशेगत अपमान से नहीं जोड़ा। हम लोग बचपन से देखते-सुनते आ रहे हैं कि जब भी लोग फुरसत में होते हैं तो अंताक्षरी खेलते हैं। कहा जाता है - शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। संसद के दोनों सदनों से निलंबित किये गए सदस्य संसद के बाहर समय बिताने के लिए अंताक्षरी के बजाय मिमिक्री कर रहे थे। मिमिक्री अपराध नहीं बल्कि एक कला है। मिमिक्री के माध्यम से सनाटे में, नीरसता में विनोद पैदा किया जाता है और मिमिक्री के लिए उस पात्र को चुना जाता है जो अपने समय में अपने हाव-भाव और अदाओं की वजह से सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो। मिमिक्री किसी अनाम आदर्मी की नहीं की जाती। निलंबित सांसदों की जमात ने इस बार मिमिक्री के लिए माननीय उपराष्ट्रपति को चुना। लेकिन वे इस चुनाव से खुश होने के बजाय आहत हो गये। उन्होंने ध्यानवाद देने के बजाय विपक्षी सांसदों पर अपमान करने का आरोप मढ़ दिया और मजा ये कि उनके टसुए पौँछेने के लिए राष्ट्रपति, पर्णानंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, से लेकर सत्तारूढ़ दल की पूरी फौज कमल लेकर कंपवार्ड नज़र आने लगी।

लालूल करतारबुद्ध नजर आन लगा।
मिमकी काण्ड को लेकर समूचा दृश्य हास्यास्पद बन गया है। जो सभापति सदन के भीतर सदस्यों को संरक्षण देने के बजाय सत्तारूढ़ दल की कठुपुतली की तरह काम करता हो उसे अचानक अपने पद, जाति और पेशे के अमाना का बोध हो जाये तो आप क्या कहेंगे? निलंबित सदस्य सदन के बाहर हैं और सदन के बाहर की गयी कोई कार्रवाई सभापति के दायरे में नहीं आती। उनके दायरे में जो आता है वो उन्होंने अब तक किया नहीं। वे एक बेरहम संरक्षक के रूप में सामने आये हैं। सभापति के रूप में उन्होंने विषय को कभी संरक्षण दिया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा समाज होगा जिसमें हास्य-व्यंयांकन और विनोद के लिए स्थान न हो, शायद ही ऐसा कोई समाज होगा जो इस विधा को अपराध मानता हो। हम तो उस समाज से आते हैं जहाँ हास्य-व्यंयांकन सानातन संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ हरि को भी व्यग्र वचनों का इस्तेमाल करने की आजादी दी गयी है। आम आदमी का तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और लोकतात्रिक औजार है। आज के सत्तारूढ़ दल ने देश के संसदीय इतिहास को न पढ़ा है न देखा है। भाजपा का तो जन्म ही 1980 में हुआ है और आज की भाजपा तो 2014 में जन्मी है। उसे संसदीय हास्य परमारों का बोध कैसे हो सकता है?

हैं, मैं तो कहता हूँ कि उन्हें निलंबन के इस नए इतिहास के लेखकों से त्यागपत्र देने के लिए आदोलन चलना चाहिए, क्योंकि सभी ने मिलकर संसदीय परम्पराओं का गला धोंटा है। अपने दल के परमविनोदी नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजेपेही की आत्मा को आहत किया है। ससद लठती से नहीं चलती कायदे कानूनों से चलते हैं। सभापति के पास निलंबन का अधिकार है तो बहाली का भी अधिकार है। सभापति सदन के हर सदस्य के सरक्षक हैं न कि केवल सत्तारूढ़ दल के। और जो सभापति कठपुतली बनते हैं, वे न सिर्फ अपने पट की गरिमा को कल्कित करते हैं बल्कि हमेशा के लिए इतिहास में एक खलनायक की तरह दर्ज किये जाते हैं। अर्थात् दो आज्ञ के नायक अन्यान्य खलनायक बन गए हैं।

किया जाए है। मुख्य साजों का नवाक अचानक खलनायक बन गए हैं। आपका जनकार हरानी होगी कि मिमक्री को लेकर असंबोधनशीलता प्रिष्ठजे एक दशक में ही बढ़ी है। अब ये केवल नेताओं का विशेषाधिकार हो गया है। खासतौर पर सत्तारूप दल के नेताओं का विशेषाधिकार। और कोई मिमक्री ताराहै तो उसे अपराध माना जाता है। हमारे सूबे में आज की तरीख में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सबसे कुशल मिमक्री कलाकार हैं। एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के पास ये तमाम हुआं करता था। कभी सदन में पीलू मारी होते थे इसी भूमिका में। वे सातीं और रोती संसद को भी अपने हास्यबोध से जागृत कर देते थे लेकिन उनके समय में कभी कोई सभापति आहत नहीं हुआ। आज के सभापति तो छुर्मुझ के पौधे हो गए हैं। यानि एक मिमक्री से उनकी जाति, वर्ग और पद का अपमान हो जाता है। ऐसे छुर्मुझ के पौधे जब सर्वैधानिक पद पर बैठकर किसी महिला मुख्यमंत्री का अपमान करते हैं तब अपने आपको गैरवान्वित महसूस करते हैं और इसी के आधार पर सियासत में पदोन्निती भी पाते हैं। लेकिन ये एक अलग मसला है। आज का मसला ये है कि क्या इस देश में कोई किसी की मिमक्री नहीं करेगा। और अगर करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जायेगा। मुझे याद है कि मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में श्याम रंगीला नाम के एक मिमक्री कलाकार के साथ यही सब हुआ। उसे मोदी और शाह की मिमक्री करने पर जेल जाना पड़ा और उसपर धारा-14 लंगी दंगा करने और अश्वीलता फैलाने की। श्याम रंगीला अकेला नहीं है। फिल्म और टेलीविजन जगत के अनेक हास्य कलाकार इस तरह की असहिष्णुता के शिकार हो चुके हैं। दुर्भाग्य ये है कि देश के इस हास्य बोध को माननीय अदालतों का भी संरक्षण नहीं मिलता। आज मिमक्री को लेकर उत्तर लोग इटली के नहीं उस नागपुर के हैं जो हरिंशंकर परसाई के व्यंग्य को नहीं पचा पाते थे और अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़े करते हैं।

દ્વાર્થી સાંસદોને સંસદ કો મજાક બનાકર રખ દિયા

उस संघर्ष जा गया है कि हांगेर संघ सांसद इस बात पर व्यापन द किस संसदीय लोकप्रत्र का फैसला नहीं लिखा जा सकता है। अन्यथा जनता ही उसका उपहास करने लगेगी। हमारे सांसदों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे किस तरह की विवासत छोड़ कर जा रहे हैं। क्या वे संसद को इसके पातन के भार के नीचे ढाने देंगे? आज जो हो रहा है, वो हम देख नहीं रहे हैं। उम्मीद है कि देश के सांसदों को, सांसद घलाने वालों को इस बात का भान जल्द हो कि देश का नागरिक उन्हें किंतु नी उम्मीद के साथ देखता है। साथ ही उन्हें कई मौकों पर उदाहरण की तरह देखता है... पिछले कुछ दिनों से संसद में जो कुछ हो रहा है, उससे देश निराश है। संसद घलाकर ही सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब सही ढंग से दे सकती है। हंगामे के माहौल में सांसदों को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता। कोई बच्चा भी समझ सकता है वेल में जाकर नारेबाजी और हंगामा कर सदन की कार्यवाही रोकने से कैसे विरोध जताया जा सकता है। अच्छी बात तो तब कहीं जाएगी, जब आप अपने सवाल साफ-साफ रखें और सरकार साफ-साफ जवाब दे पाए।



प्रियका सारभ लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

नारेबाजी करना, एक-दूसरे पर निजी कटाक्ष करना यहां तक कि कई बार हाथापाई पर उतारू हो जाना आज संसद की आम तस्वीर है। अखिर सियासी पार्टियों और सांसदों का बर्ताव इतना आराजक बयों हो गया है? क्या आज पार्टियों के निहित स्थाथों ने संसद को मजाक बनाकर रख दिया है। अब समझ आ गया है कि हमारे सभी सांसद इस बात पर ध्यान दें कि संसदीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। अन्यथा जनता ही उसका उपहास करने लगेगी। हमारे सांसदों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे किस तरह की विरासत छोड़ कर जा रहे हैं। क्या वे संसद को इसके पतन के भार के नीचे ढाबने देंगे? आज जो हो रहा है, वो हम देखा ही रहे हैं। उम्मीद है कि देश के सांसदों को, सांसद चलाने वालों को इस बात का भान जल्द हो कि देश का नागरिक उन्हें कितनी उम्मीद के साथ देखता है। साथ ही उन्हें कई मौकों पर उदाहरण की तरह रखता है...

पिछले कुछ दिनों से संसद में जो कुछ हो रहा है, उससे देश निराश है। संसद चलाकर ही सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब सही ढंग से दे सकती है। हाँगमे के का मैका ही नहीं मिलता। कोई बच्चा भी समझ सकता है वेल में जाकर नारेबाजी और हंगामा कर सदन की कार्यवाही रोकने से कैसे विरोध जताया जा सकता है। अच्छी बात तो तब कहीं जाएगी, जब आप अपने सवाल साफ-साफ रखें और सरकार साफ-साफ जवाब दे पाए। लेकिन इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि संसद की कार्रवाई में बाधा अपवाद की बजाय नियम बन गया है और हमारे राजनेताओं को इस पर कोई पछतावा नहीं होता है। पिछले वर्षों में यह गिरावट बड़ी तेजी से आई है। संसद एक-दूसरे पर चिल्लाते हैं, विधायी कागजों को छीनकर फाड़ देते हैं, छोटे से मुद्दे पर सदन के बीच-बीच आ जाते हैं। पिछले वर्षों में ज्यादातर विधेयकों को बिना चर्चा के ही पारित किया गया है। यह संसदीय प्रणाली का दुरुपयग है। अब विधीय पार्टियों और कुछ सांसदों ने संसद की दुर्गति कर रखी है। दोनों सदनों में निजी एजेंडों को लेकर अनुत्पादक हंगामा क कार्यवाही ठप करा देना आम बात है। संसद में शोर-शराबा, वेल में जाकर नारेबाजी करना, एक-दूसरे पर निजी कटाक्ष करना यहां तक कि कई बार हाथापाई पर उतारू हो आखिर सियासी पार्टियों और सांसदों बर्ताव इतना आराजक बयों हो गया क्या आज पार्टियों के निहित स्थाथों संसद को मजाक बनाकर रख दिया सांसदों के रखैये को देखते हुए ल नहीं है कि उसकी मंशा देश के विवर की योजनाएं बनने देने की है। ऐसा रहा है कि सांसदों ने पूरे संसदीय लोकों को बंधक बना लिया है। क्यों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आजकल टीवी पर लाइव दिखाई जा रही है, लिहाजा देश का आम आदमी पर वह सब कुछ देखता है, जो संसद रोज हो रहा है। अखिर सांसद लोगों सामने अपनी क्या छवि पेश कर रहे जरा सोचिए कि देश के लोगों के माझे आपकी क्या छवि बनती जा रही है? सच है कि इस गिरावट का कारण यह कि राजनीति आज संख्या का खेल गई है जिसके चलते क्षेत्रीय क्षत्रप अमनमर्जी करने के लिए दबाव डालते हैं। वे न केवल दादिमारी की राजनीति में विश्वास करते हैं अपितु सफल संसद के पैमाने को हासिसकी लात उसकी भैसङ्घ भी बनाते हैं। आज विवर वस्तु की बजाय आकार महत्वपूर्ण गया है जिसके चलते संसद में ग

का मौका ही नहीं मिलता। कई बच्चे भी समझ सकता है वेल में जाकर नरेबाजी और हंगामा कर सदन की कार्यवाही रोकने से कैसे विरोध जताया जा सकता है। अच्छी बात तो तब कही जाएगी, जब आप अपने सवाल साफ-साफ रखें और सरकार साफ-साफ जवाब दे पाए। लेकिन इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि संसद की कार्रवाई में बाधा अपवाद की बजाय नियम बन गया है और हमारे राजनेताओं को इस पर कोई पछतावा नहीं होता है। पिछले वर्षों में यह गिरावट बड़ी तेजी से आई है। संसद एक-दूसरे पर चिल्लाते हैं, विधायी कागजों को छीनकर फाड़ देते हैं, छेटे से मुद्रा पर सदन के बीचों-बीच आ जाते हैं। पिछले वर्षों में ज्यादातर विधेयकों को बिना चर्चा के ही पारित किया गया है। यह संसदीय प्रणाली का दुरुपयोग है। अब विषयी पर्यावर्त्यों और कछ सांसदों ने संसद की दुर्गति कर रखी है। दोनों सदनों में निजी एजेंडों को लेकर अनुत्पादक हंगामा कर कार्यवाही ठप करा देना आम बात है। संसद में शेर-शराबा, वेल में जाकर नरेबाजी करना, एक-दूसरे पर निजी कठोर्क करना यहां तक कि कई बार हाथापाई पर उतार रहे आखिर सियासी पार्टी इतना अराजिक व्या आज पर्यावर्त्यों संसद को मजाक न सांसदों के रवैये न नहीं है कि उसकी की योजनाएं बनने की बधक बना लोकसभा और राज आजकल टीवी पर है, लिहाजा देश व वह सब कुछ देख रोज हो रहा है। सामने अपनी कथा जरा सोचिए कि देख आपकी कथा छवि व सच है कि इस गिरावट की राजनीति आज गई है जिसके चलाने मनमनजी करने के हैं। वे न केवल दम में विश्वास करते हैं सत्र के पैमाने के उसकी भैंसली भी ब वस्तु की बजाय त गया है जिसके च

टियों और सांसदों
नक क्यों हो गया
के निहित स्वाथों
बनाकर रख दिया
को देखते हुए ल
मंश देश के विव
देने की है। ऐसा
पूरे संसदीय लोक
लिया है। क्यों
न्यसभा की कार्यवी
र लाइव दिखाई ज
का आप अदामी
वता है, जो संसद
खिर संसद लोगों
छिपि पेश कर रहे
श के लोगों के मध्य
बनती जा रही है?
वक्त का कारण य
संख्या का खेल
ते क्षेत्रीय क्षत्रप अ
लिए दबाव डां
दामिरी की राजन
अपनु सफल स
द्वायसकी ला
नाते हैं। आज वि
माकर महत्वपूर्ण
लते संसद में ग

का लिले हैं। इसलिए यह गरिती संस्कृति और नैतिक मूल्यों का राजनीति का प्रभाव वाली विषय सामग्री नहीं मिल सकता। यहाँ लगातार ऐसा लगता है कि महज एक स्कोरिंग क्लब वर्गी है। बहुतों को पता होगा यह एक मिनट की कार्यवाही पर उसकी रूपण खर्च हो जाते हैं। इस तरह की कार्यवाही पर ३ करोड़ रुपए का खर्च आता है। दिन कार्यवाही लंबी चलती है और बढ़ जाता है। उसके कारण यह पैसा आता कहाँ से आता है? किंतु देश के आम लोगों को आता है। लोकतंत्र में इससे बदलता है क्या मजाक होगा कि संसद का लगातार ठप रहे या फिर कर हो गंगामा होता रहे, फिर संसद में छह करोड़ रुपण खर्च हो सकती है? हजारों गांवों व संसद की एक दिन की कार्यवाही लगातार रुपण खर्च से बदल होने वाले खर्च से बदल लाखों गरीब लड़कियों को सकती है। लघु और कुटीर बन हजारों नौजवानों की किसी

सोचते। विकास की योजनाएं भले न बनें, व्यक्तिगत हित जरूर सुधरने चाहिए। क्या सांसद देश से ऊपर हो गए हैं?

एक बात और सरे सांसद हांगमेबाज हों- ऐसी बात नहीं है। जो कामकाज को लेकर गंभीर हैं, वे कुछ नहीं कर पाते। सबाल है कि सांसद हर बार माहौल क्यों नहीं बनाते? क्या सांसद केवल हांगमा करने के लिए ही पहुंचते हैं? सांसदों ने लोकसभा को पंग बना कर रख दिया है। हकीकत यह है कि लोकतंत्र का लोक यानी देश की जनता लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पर करती है। ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदन को लोक के सदन यानी लोकसभा की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोकसभा में हुए हर काम में अङ्गा डाल दिया जाए। लोकसभा में तय दिनों में सभी सांसदों की तीन-तीन मेंट ही सही, अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बोलने दिया जाए। बार-बार हांगमा करने वाले सांसदों को चिन्हित किया जाए और उनकी सूची प्रचारित कराई जाए। ऐसे नियम बनाए जाएं कि वेल में आने वा पर्चा लहराने या दूसरा किसी भी कि स्म का हांगमा करने वाले सांसद के खिलाफ खुद-ब-खुद कोई तय कार्यवाही हो बाद दोबारा सदन में क्यों आ जाते हैं केवल दिखावा करने के लिए ऐसा करते हैं, उन्हें देश के विकास से कोई लेनदेना नहीं है।

वे सांसद में कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उधर उनके लोकसभा क्षेत्र कर्मज जनता त्रस्त, क्योंकि वे उनकी समस्याओं सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि संसद में केवल हांगमा हो रहा है। इसलिए संसद को अखाड़ा बनने से रोके। नेतृत्व को भी अपनी बात समझाएं, उनके हर गलत करने के लिए लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का गरिमा बचाए रखना सांसदों का प्रथमान्तर काम है। संसद को महत्वहीन बनाने वे खतरनाक आयामों को शायद ये लोक नहीं समझते हैं। हमारी संसद हमारी राष्ट्र की आधारशिला है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जिससे अपेक्षण की जाती है कि वह हमारे राष्ट्रीय वित्त पर संप्रभु निरगानी रखे। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और सरकार का अस्तित्व उस पर लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। अतः समय आ गय है कि हमारे सभी सांसद इस बात पर ध्यान दें कि संसदीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है।

इसान यह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि धर्म-आस्था व अंधविश्वास के इस घालमेल ने मनुष्य को कितना क्रूर, अमानवीय व हिंसक बना दिया है? रोज कहीं न कर्ही गांव-मुहल्ले के बलशाली लोग किसी न किसी गरीब परिवार के किसी व्यक्ति को खासकर महिला को चुड़ैल, भूतनी या डायन बता कर उसपर मनमाना अत्याचार करते हैं। किसी भी दीप या रंग की जारी रखते हैं तो किसी भी दीप या रंग की जारी रखते हैं।

करत है। किंसा का पाट पाटकर हत्या कर दा जाता है तो किंसा का रास्सया या लाह का जरजरा से जकड़कर किसी पेढ़ से बाँध दिया जाता है। उसे भूखा प्यासा रखकर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी अनेक पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म भी किये जाते हैं। ऐसे मामलों में नाममात्र कार्रवाई भी होती है। परन्तु इस देश में जितना न्याय किसी गरीब को मिलता है वहां भी उतना ही न्याय कि सी पीड़ित व प्रताड़ित व्यक्ति को भी मिलता है अर्थात् नाममात्र य बिल्कुल नहीं। इसी अधिविश्वास की श्रीणी में आती है तांत्रिक विद्या। इस विद्या पर भी धर्म व अन्धविश्वास क जाचा छढ़ाकर हमारे देश में जमकर हैवानियत का खेल खेला जा रहा है। इसी की आड़ में बलात्कार, हत्या, धन ऐंठना, लौक मेलिंग आदि न जाने क्या क्या हो रहा है। शत प्रतिशत झूट व पाखंड पर आधारित तांत्रिक विद्या क इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र है कि प्रायः पढ़े लिखे लोग यहाँ तक कि मत्री व अधिकारी भी किसी न कि सी लालचवश इस जाल में फँस जाते हैं। देश में तमाम ऐसे तांत्रिक हुए हैं जिनकी पहुँच सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक भी रही है।



लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं

तकर उसा देश का लागा का। वह भी समझा दिया जाता है कि यदि तीसरी पारी में सत्ता हासिल हुई तो देश को विश्व की तीसरी महाशक्ति बना देंगे। शायद इहीं ह्याराशन लाभार्थीयों ह्य के बल पर? जहाँ चंद्रयान छोड़े जा रहे हों विकास की नित नई गाथायें लिखने के दावे किये जा रहे हैं। उसी देश में आज के आधुनिक व वैज्ञानिक दौर में अंधविश्वास व पाखंड से भरी ऐसे अनेक खबरें आये दिन सुनाई देती हैं जिन्हें देख पढ़ कर रुह काँप जाती है। इंसान यह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि धर्म-आस्था व अंधविश्वास के इस घालमेल ने मनुष्य को कितना क्रूर, अमानवीय व हिंसक बना दिया है? रोज कहीं न कहीं गांव-मुहल्ले के बलशाली लोग किसी न किसी गरीब परिवार के किसी व्यक्ति को खासकर महिला को चुड़ैल, भूतनी या डायन बता कर उसपर मनमाना अत्याचार करते हैं। किसी की पीट पीटकर हत्या कर दी जाती है तो किसी को रस्सियां या लोहे रखकर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा अनेक पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म भी किये जाते हैं। ऐसे मामलों में नाममात्र कर्कार्वाई भी होती है। परन्तु इस देश में जितना न्याय किसी गरीब को मिलता है यहाँ भी उतना ही न्याय किसी पीड़ित व प्रताड़ित व्यक्ति को भी मिलता है अर्थात् नाममात्र या बिल्कुल नहीं।

इसी अंधविश्वास की श्रणी में आती है तात्त्विक विद्या। इस विद्या पर भी धर्म व अंधविश्वास का जामा चढ़ाकर हमारे देश में जमकर है वानियत का खेल खेला जा रहा है। इसी की आड़ में बलात्कार, हत्या, धन ऐंठना, ब्लैक मेलिंग आदि न जाने क्या क्या हो रहा है। शत प्रतिशत झूठ व पाखंड पर आधारित तात्त्विक विद्या का इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र है कि प्रायः पढ़े लिखे लोग यहाँ तक कि मंत्री व अधिकारी भी किसी न किसी लालचवश इस जाल में फँस जाते हैं। देश में तमाम ऐसे तात्त्विक हुए हैं जिनकी पहुँच सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक भी रही है। परन्तु चूँकि इस तरह की अंधविश्वास, झूठ व का नाममात्र ताककता व तकशाल नहीं होती इसलिये झूठ आधारित इस्वयंभू विद्या को जड़मूल से समाकरने में ही हमारे समाज का भ्रष्ट है। परन्तु बड़े आश्वर्य की बात तो यह है कि चुड़ैल, भूतनी या डायन त तात्त्विक विद्या के चक्करों में सदियों से उलझे हमारे देश की सरकारें। इस ह्यानासूर ह्य रुपी अंधविश्वास पाखण्ड से देश को निजात नहीं दिया सकीं। इसका कारण भी बड़ा रोचक है। दरअसल सरकारें व इसमें शामिल तमाम शातिर नेता चाहते भी यही कि देश की भौली भाली जनता इन बे सिर पैर की बातों में उलझी रहे अंधविश्वास में डूबी रहे। विज्ञान, त और शिक्षा की बात ही न करे। त मन्त्र और छू मन्त्र के बल पर अप समस्याओं का समाधान तलाशे। ऐसे करने से अंधविश्वास को बढ़ाव व संरक्षण देने वाले तमाम निठल लोगों को रोजगार मिल जाता है। ऐसे लोगों पर धर्म की अफीम का गहरा र चढ़ता है। बाद में यही लोग 80 करों

त्रिलोक विजय का इतिहास ५

मुक्ति म राशन दन का बादा किया ह। परन्तु सत्ता के इस स्वार्थ और लोगों का अशिक्षित रखने के चलते इस देश में कुछ ऐसी घटनायें भी हो जाती हैं जिससे हमारे देश की न केवल बदनामी होती है बल्कि दुनिया यह भी सोचने के लिये मजबूर हो जाती है कि चंद्रयान छोड़ने वाले देश में अधिखर हो क्या रहा है? मिसाल के तौर पर गत दिनों कानपुर देहात के घाटम पुर इलाके के भद्रस गांव की एक क्रूरतम घटना को लेकर एक अदालती फैसला आया जिसने तीन वर्ष पूर्व यानी 14 नवंबर 2020 की भयावह घटना की याद फिर ताजा कर दी। दरअसल कानपुर देहात के घाटम पुर इलाके के भद्रस गांव में 14 नवंबर 2020 को छः वर्ष की एक मासूम बच्ची का अपहरण कर पहले उसके साथ रेप किया गया फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं बल्कि अरोपियों ने वहशीपन की सारी हड्डें पार करते हुए उसका कलेजा निकालकर रोटी के साथ खाया था। पढ़ा करन के लिये यह उपयोग बताया था। इसी मामले में स्थानीय अदालत ने चार दोषियों को सजा सुनाई है। तीन साल तक चली सुनवाई के बाद पिछले दिनों कानपुर देहात के अपर जिला जज शमीम रिजवी की अदालत ने आरोपी दंपती परशुराम व सुनैना को आजीवन कारावास और 20-20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहाँ दंपति के भतीजे अंकुल और उसके साथी वीरेन को पूरे जीवन काल का कारावास और 45-45 हजार अर्थदंड का लगाया है। यह इस देश की पहली घटना नहीं है। ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, सामूहिक आत्म हत्याएं तक देश की राजधानी दिल्ली में हो चुकी हैं। परन्तु इन सबके बावजूद तांत्रिकों का व्यवसाय फल फूल रहा है। तांत्रिक विद्या व व्यवसाय का प्रचार करने वाले तमाम पोस्टर हैंडबिल पम्पलेट सार्वजनिक स्थानों, बसों ट्रेन्स पार्कों में यहाँ वहाँ चिपके देखे जा सकते हैं। इनमें उनके संपर्क नंबर और पता आधारित इस व्यवसाय का फलत पूलत देखती रहती है। और देखे भई क्यों न? जब स्वयं सरकार के मंत्री नींबू और हरी मिर्च लटकाकर टोटके करत फिरें, पूजा पाठ दुआ ताबीज का सहारा लेकर अवैज्ञानिकता के बढ़ावा देते दिखाई दें तो इसका मकसद साफ है कि ऐसे सभी अंधविश्वासी व पाखंडपूर्ण गतिविधियों को सरकार के संरक्षण हासिल है। और सरकार स्वयं चाहती है कि लोग आज के आधुनिक व वैज्ञानिक दौर में भी अंधविश्वास व पाखंड में उलझे रहें। अन्यथा एक कुशल, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाली सरकार को तो देशवासियों को अंधविश्वास व पाखंड से मुक्ति दिलाने व गरिबों कर्मजान माल सुरक्षित करने हेतु पूरे देश में त्रंत्र मन्त्र विद्या और दूसरे सभी ढोंग झाड़ा, ताबीज, कण्डा आदि तत्काल प्रभाव से प्रतिबर्धित कर देना चाहिये और लोगों को अंधविश्वास से दूर रखना तथा उनमें वैज्ञानिक सोच क संचार करना चाहिये।

दराज पहाड़ी इलाकों पर आबाद हैं। इनमें से ज्यादातर पंचायतें सर्विंगों के चार महीने बर्फ से ढकी रहती हैं और सर्विंगों के बीच अंतर से अंतर तक नहीं है। यह उनके आर्थिक माध्यम है। यह उनके आर्थिक सम्भविता का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र तीन महीने तक बर्फ के कारण बंद रहता है। यदि उनकी इन सभी समस्याओं का उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये समस्या इसलिए भी गंभीर हो गई है, क्योंकि इन मवेशियों के लिए दवा मिलना भी बहुत दूर है।

महाजन को पहले ही सचित कर दिया जाना चाहिए। वह हमारी पीड़ा की समझे और नियंत्रण के लिए दबाव लेना चाहिए।

जानलवा ब
वहीं दसरी

जम्मू के डोडा स्थित पहाड़ी इलाकों में मवेशियों के बीच एक अज्ञात बीमारी ने कोहराम मचा रखा है। जिसने अब तक कई पालतु मवेशियों की जाने ले ली है। ये मवेशी गरीबों की आय का प्रमुख स्रोत हैं। ऐसे में इन जानवरों की मौत उन्हें अर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। क्षेत्र का पशु चिकित्सा विभाग भी अभी तक इस बीमारी के कारणों और इसके समुचित इलाज का पता लगाने में असफल रहा है। जात हो कि डोडा जिले के ठाठरी उपमण्डल में तीन तहसीलें हैं। इन तीनों तहसीलों के प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहीं यहां का विकास कार्य भी ठप हो जाता है। जिससे प्रशासनिक स्तर पर ग्रामीणों को कोई मदद नहीं मिल पाती है। वर्षमान में, इन क्षेत्रों के लोगों की आज सबसे बड़ी समस्या मवेशियों में फैल रही यह अज्ञात बीमारी है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई कि इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और मवेशियों की जान बचाने के इंतजाम किया जाए। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है और न ही प्रशासन द्वारा एक सपाह घहले उनके मवेशियों को बुखार आता है। जिससे धीरे धीरे वह खाना पीना बंद कर देते हैं और फिर कछु ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। गैरतलब है कि इन दूर दराज ग्रामीण कई घर ऐसे हैं जहां सैकड़ों की संख्या में मवेशी पाले जाते हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई कि इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और मवेशियों की जान बचाने के इंतजाम किया जाए। लेकिन इस इलाके में फैलती है, जिसमें सैकड़ों मवेशियों की जान चली जाती है। जबकि यह मवेशी इन पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। उन्होंने कहा कि हर घर में कम से कम दो भैंस और एक गाय पाली जाती हैं। जिसका न केवल दृढ़ बेचकर बल्कि उसका गोबर भी बेच कर यह ग्रामीण अपनी आय में वृद्धि करता है।

जनजीवन प्रभावित नहीं हो सकता है। वहीं, एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता आदिल हुसैन कहते हैं कि मवेशियों के बीच यह अज्ञात महामारी हर साल इस इलाके में फैलती है, जिसमें सैकड़ों मवेशियों की जान चली जाती है। जबकि यह मवेशी इन पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। उन्होंने कहा कि हर घर में कम से कम दो भैंस और एक गाय पाली जाती है। जिसका न केवल दृढ़ बेचकर बल्कि उसका गोबर भी बेच कर यह ग्रामीण अपनी आय में वृद्धि करता है।

भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्थानीय किसान खेतों में देसी खाद डालने के लिए इन मवेशियों का गोबर खरीदते हैं और खेतों में रासायनिक खाद की जगह उपयोग करते हैं। एक अन्य स्थानीय महिला सायमा बानो ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहती है कि बीमारी से मवेशियों की मौत से होने वाले नुकसान का कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है। जबकि प्रशासन को इस वर्ष भी जिस प्रकार से यह बीमारी के फैल रही है उससे यह संकेत मिलता है। जबकि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि गरीबों के नुकसान की पूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोगों के लिए बेचकर बल्कि उसका गोबर भी बेच कर यह ग्रामीण अपनी आय में वृद्धि करता है।

